



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आश्विन 1940 (श10)

(सं0 पटना 904) पटना, वृहस्पतिवार, 4 अक्टूबर 2018

सं0 ग्रा0वि0-6/कोर्ट केस-25/2008-391415

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

28 सितम्बर 2018

विषय :- सी.डब्लू.जे.सी. सं0-10653/2008 अनिरुद्ध झा बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य के मामले में पारित निर्णय के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भागलपुर के तत्कालीन सहायक, श्री अनिरुद्ध झा की सेवा का सरकारी सेवक के रूप में समायोजन के संबंध में ।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भागलपुर के तत्कालीन सहायक, श्री अनिरुद्ध झा द्वारा केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों के आलोक में अपनी सेवा सरकारी सेवक के रूप में समायोजित करने के लिए सी.डब्लू.जे.सी. सं0-10653/2008 दायर किया गया था । इसमें दिनांक-27.04.2015 को न्यायादेश पारित है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

“The State Government is directed to pass appropriate orders absorbing the petitioner in permanent government service pursuant to the government’s decisions as noted above of the year 2003 and 2006 and grant all consequential benefits to the petitioner, even though, petitioner has since superannuated. He has filed the writ petition while he was in service.”

(2) उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एल.पी.ए. सं0-2082/2015 दायर किया गया, जो दिनांक-13.03.2018 को खारिज कर दिया गया । पुनः एल.पी.ए. सं0-2082/2015 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP डायरी सं0-27689/2018 द्वारा किया गया, जो दिनांक 04.09.2018 को खारिज कर दिया गया ।

(3) फलतः सी.डब्लू.जे.सी. सं0-10653/2008 में पारित आदेश आलोक में श्री अनिरुद्ध झा, जो जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भागलपुर से दिनांक 30.09.2010 को सेवा निवृत्ति हुए, की सेवा निम्न शर्तों के अधीन सरकारी सेवक के रूप में समायोजित किए जाने का निर्णय लिया जाता है:-

- क. जिला पदाधिकारी, भागलपुर समाहरणालय संवर्ग के उच्च वर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर श्री झा का समायोजन करेंगे ।
- ख. यह समायोजन दिनांक 21.07.2008 की भूतलक्षी तिथि (श्री झा द्वारा रिट याचिका दायर करने की तिथि) से प्रभावी होगा ।
- ग. समायोजन की तिथि (21.07.2008) से सेवानिवृत्ति की तिथि (30.09.2010) तक सरकारी सेवक को नियमानुसार अनुमान्य वेतनादि का लाभ इन्हें अनुमान्य होगा। समायोजन की तिथि से ये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भागलपुर में प्रतिनियुक्त समझे जाएँगे ।
- घ. जिला पदाधिकारी, भागलपुर द्वारा समायोजन एवं देय लाभों के भुगतान हेतु एतदर्थ आदेश निर्गत करेंगे ।
- ङ. इस समायोजन हेतु नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा शिथिल समझी जायेगी ।
- च. समायोजन की तिथि के पूर्व के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की कार्य अवधि में किसी प्रकार की देनदारी/बकाया का दायित्व राज्य सरकार का नहीं होगा ।
- छ. वित्त विभाग के संकल्प सं0-796 दिनांक 02.02.2018 के आलोक में समायोजित कर्मों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्राप्त हो रहा वेतन समायोजित पद के वेतनमान में संरक्षणीय होगा अर्थात् पैतृक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में धारित पद हेतु प्रभावी वेतनमान संरक्षणीय नहीं होगा, बल्कि कुल प्राप्त वेतन ही संरक्षणीय होगा ।
- ज. पेंशन एवं ACP/MACP के प्रयोजनार्थ समायोजन पूर्व की जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की सेवाअवधि गणनीय नहीं होगी । समायोजन की तिथि से अनुमान्य लाभों के लिए कालावधि गणनीय होगी तथा सरकारी सेवक के रूप में सेवा राज्य सरकार की नई पेंशन योजना-2005 से आच्छादित होगी ।
- झ. समायोजित कर्मों की वरीयता का निर्धारण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वरीयता निर्धारण संबंधी संकल्पों/ परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा ।
- ञ. समायोजन के पश्चात कर्मों की प्रोन्नति, समायोजित पद के संवर्गीय नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में होगी ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 904-571+100-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>